

भारत सरकार  
इस्पात मंत्रालय  
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 319  
05 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

जेएसपीएल के साथ आरआईएनएल का समझौता ज्ञापन

319. श्री जी.वी.एल. नरसिंहा राव:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि आरआईएनएल ने तीसरी ब्लास्ट फर्नेस के संचालन के लिए जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;
- (ख) जेएसपीएल के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की नियम और शर्तें क्या-क्या हैं;
- (ग) क्या आरआईएनएल ने सेल के साथ इसी प्रकार का समझौता ज्ञापन करने के लिए कोई प्रयास किए हैं और इस पर सेल की क्या प्रतिक्रिया है;
- (घ) क्या आरआईएनएल द्वारा मांगी गई रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) में अन्य भागीदारों को भी यही शर्तें पेश की गई थीं;
- (ङ.) क्या जेएसपीएल के साथ समझौता ज्ञापन के पश्चात आरआईएनएल के उत्पादन और लाभप्रदता में सुधार होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) आरआईएनएल की कार्यशील पूंजी की स्थिति में सुधार लाने के लिए अन्य क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री फगगन सिंह कुलस्ते)

(क)से(ङ.): आरआईएनएल ने, कन्वर्जन मॉडल पर कार्यशील पूंजी/कच्ची सामग्री की सहायता के आधार पर कारोबारी प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) तथा खुली निविदाएं क्षमतावान कंपनियों, जिनमें सेल भी शामिल है, को जारी की थीं। आरआईएनएल द्वारा परस्पर सहमत वाणिज्यिक शर्तों के आधार पर उचित निविदा प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जेएसपीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(च): आरआईएनएल की कच्ची सामग्री की लागत को कम करने के उद्देश्य से इस्पात मंत्रालय ने आरआईएनएल को घरेलू कोकिंग कोयला तथा थर्मल कोयले की आपूर्ति का मामला कोयला मंत्रालय के साथ उठाया है। इस्पात मंत्रालय ने आरक्षण मार्ग के माध्यम से लौह अयस्क ब्लॉक के आवंटन के लिए ओडिशा राज्य सरकार से भी अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, आरआईएनएल ने अपने वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए समय-समय पर निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) मूल्य वर्धित इस्पात के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि तथा उच्चतर प्राप्ति को हासिल करने के उद्देश्य से बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद मिश्रण के इष्टतमीकरण के द्वारा प्रचालन लागत में कमी लाई जा रही है और लागत को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है एवं राजस्व का अधिकतमीकरण किया जा रहा है।

(ii) लागत में कमी के लिए कोल ब्लेंड में घरेलू कोकिंग कोयले का अधिकतमीकरण करना।

(iii) उधारी की सीमाओं को बढ़ाने के लिए बैंको से अनुरोध किया जा रहा है।